किया जाता है जो अधिकतम सीमा से कम पर काम कर रहे हैं।

Visit of Indian Telecommunication Mission to Pakistan

2099. SHRI ARANGIL SREEDHARAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether an Indian Telecommunications Mission visited Pakistan recently to settle certain telephone-telegraph problems as a sequel to the cross country decision of SAARC:

(b) if so, what are the salient features of the decisions taken; and

(c) what follow up steps are being taken by Government of India in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) An Indian Telecommunication Team consisting of four officers visited Pakistan from 14th to 16th February, 1989 for a routine Telecommunication operational coordination meeting not as a sequel to the cross decision of SAARC.

(b) For improvement of performance, both sides agreed to take regular tests, exchange traffic data and monitor efficiency of the circuits. It was also agreed to close down some manual circuits having low volume of traffic. Depending upon traffic, both sides agreed to examine and augment automatic service between the two countries. Both sides agreed to exchange regular accounting information and carry out regular settlement. It has been agreed to consider the adoption of uniform accounting rate for telephone calls both on terrestrial and Satellite media.

(c) Steps are being taken to implement the decisions taken as per para 'b' above.

Technology transfer in the Chemical and Petrochemical industries

2100. SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what are the main technology transfers in the Chemical and Petrochemical Industries during the year 1988;

(b) what is the total amount spent on the import of the technologies;

(c) whether any of these technologies was part of a foreign collaboration; and

(d) if so, what are the details of direct transfers and those through foreign collaborations?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) and (b) In the year 1988, the main technology transfers approved by the Government, in the Chemical and Petrochemical Industries were in the field of Dyes and Dye-intermediates, Fatty Acids, Maleic Anhydride, Industrial Alcohol based on beet root, Hydrogen Peroxide, Polymers, Linear Alkyl Benzene, Synthetic Fibres and Intermediates. These approvals amount to foreign exchange outgo of about Rs. 110 crores on account of lump-sum payments for know-how and engineering packages.

(c) Yes Sir.

(d) Details of all technology transfers for Chemicals approved in 1988 are given in Annexure I [*See* Apprendix CXLIX, Annexure no 116]. Those where lquity participation is indicated, involve foreign collaboration and the rest are only direct technology transfers. Similar figures for the Petrochemical Sector are being collected.

नये सरकारी निगम/सरकारी कम्पनियां

2101**डा. रत्नाकर पाण्डेय :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कौन-कौन से नये सरकारी निगम या सरकारी कंपनियां स्थापित की गयीं;

(ख) इनमे से कौन-कौन से सरकारी उपक्रमों का नाम हिन्दी मे रखा गया और किन-किन कम्पनियों का नाम अंग्रेजी मे रखा गया, और

(ग) क्या नियमों मे ऐसा प्रावधान है कि नये स्थापित किये जाने वाले सरकारी क्षेत्र के निगमों के नाम शुरू से ही हिन्दी मे या अन्य क्षेत्रीय भाषा मे रखे जाये और उनका प्रयोग अंग्रेजी में करते समय भी उनका अंग्रेजी रूपान्तर न किया जाये?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम: (क) 1984-85 से 1988-89 (जनवरी, 1989 तक) की अवधि के दौरान पंजीकृत सरकारी कम्पनियों के नाम अनुलग्नक में दिये गये हैं। [**देखिये** परिशिष्ट 149, अनुपल सख्या 117]

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान पंजीकृत 13 सरकारी कम्पनियों के नाम हिन्दी में है जिन्हें अनुलग्नक में चिन्हित किया गया है जबकि 109 कम्पनियों के नाम अंग्रेजी में हैं।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों मे ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अन्तर्गत नई स्थापित सरकारी कम्पनी को अपना नाम हिन्दी या अन्य प्रादेशिक भाषा में रखना अपेक्षित हो।

बोधघाट परियोजना के विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम

2102. **श्री अजीत जोगी:**
श्री पृथ्वी मांझी:

क्या ऊर्जा मंत्री 8 अगस्त, 1988 को राज्य सभा मे अतारांकित प्रश्न 1422 के दिये गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बस्तर जिले की बोधघाट परियोजना के प्रत्येक विस्थापित परिवार को बिना लागत के पाच एकड़ कृषि योग्य विकसित भूखंड (प्लाट) और एक मकान देने के संबध में बनाये गये पुनर्वास कार्यक्रम मे अब तक क्या प्रगति हुई हैं;

(ख) क्या पुनर्वास हेतु उपलब्ध भूमि की पहचान करा ली गई है और क्या इस प्रयोजनार्थ आसपास के क्षेत्रों मे पर्याप्त भूमि उपलब्ध है;

(ग) यदि हा, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत जमीन और मकान उन्हे विस्थापित करने से पहले उपलब्ध करा दिये जायेंगे?

ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) बोधघाट जल विद्युत परियोजना के लिए पुनर्वास योजना के अतर्गत विस्थापित होने वाले परिवारों को कृषि प्लाटों के रूप में आबंटित किए जाने हेतु पर्याप्त माता में कृषि-योग्य भूमि का पता लगा लिया गया है। आवास-गृहों के निर्माण के लिए तीन गांवों मे आबादी प्लाटों का निर्धारण किया गया है।

(घ) **जी हां।**

Develoment of Tidal Power

2103. SHRI CHANDRIKA PRASAD TRIPATHI:

SHRI BEKAL UTSAHI:

DR. RATNAKAR PANDEY:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have recently decided to enter the area of tidal power development in the country; and

(b) if so, what progress has been made in this regard so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALPNATH RAI): (a) and (b) Detailed investigations and studies for assessing the feasibility of a tidal power project in the Gulf of Kutch on the west coast in Gujarat were started in 1982. The studies have been completed and a feasibility report has been prepared. As per the report, which is under techno-economic evaluation, an installation of 900 MW power plant, comprising 36 units of 25 MW each, is envisaged in Gulf of Kutch. The project will be processed further only after it is found to be techno-economically viable.